

आर्थिक विकास का माप व संकेतक (Measurement and Indicators of Economic Development)—आर्थिक विकास एक सापेक्षिक शब्द है तथा इसका सम्बन्ध एक समय विशेष से न होकर दीर्घकालीन परिवर्तनों से है जिसके कारण आर्थिक विकास का एक निश्चित मापदण्ड देना अत्यन्त कठिन है। यही कारण है कि आर्थिक विकास के मापदण्ड के विषय में अर्थशास्त्रियों के विचारों में विभिन्नता रही है।

आर्थिक विकास के मापदण्ड के सम्बन्ध में प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के विचार और आधुनिक अर्थशास्त्रियों के विचार अलग-अलग हैं जैसा कि निम्नलिखित विवरण से स्पष्ट हो जायेगा :

(I) प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के विचार (Views of Classical Economists)

विभिन्न प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के आर्थिक विकास के मापदण्ड के सम्बन्ध में विभिन्न विचार निम्न प्रकार रहे हैं :

(1) वाणिज्यवादी अर्थशास्त्रियों ने उपलब्ध सोना-चाँदी की मात्रा तथा विदेशी व्यापार की मात्रा को आर्थिक विकास का मापदण्ड माना है, जबकि इस विचारधारा की सार्थकता न थी, न है।

(2) एडम स्मिथ एवं समकालीन अर्थशास्त्रियों ने शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन की मात्रा का अधिक होना ही आर्थिक विकास माना है।

(3) कार्ल मार्क्स अधिकतम सामाजिक कल्याण का आधार समाजवाद अथवा साम्यवाद को मानता है, इसलिए मार्क्स के अनुसार समाजवाद ही आर्थिक विकास का मापदण्ड है।

(4) प्रो. जे. एस. मिल ने तो सहकारिता को ही आर्थिक विकास का मापदण्ड माना है।

प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों द्वारा सुझाये गये मापदण्ड एकाकी थे और उनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था।

(II) आधुनिक अर्थशास्त्रियों के विचार (Views of Modern Economists)

आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक विकास के लिए उत्पादन के साथ-साथ वितरण को भी महत्व दिया। आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक विकास के लिए किसी एक तत्व को मापदण्ड नहीं माना। उनकी दृष्टि से आर्थिक विकास के लिए सभी आवश्यक तत्वों का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इन सब तत्वों के परिणामस्वरूप ही किसी देश में आर्थिक विकास होता है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार आर्थिक विकास के कुछ प्रमुख मापदण्ड अग्र प्रकार हैं :

1. राष्ट्रीय आय (National income)—आर्थिक विकास का माप करने के लिए हमें देश की राष्ट्रीय आय को देखना पड़ता है। किसी देश में एक वर्ष के अन्दर पैदा की गयी समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के

आधुनिक अर्थशास्त्रियों के विचार

1. राष्ट्रीय आय
2. प्रति व्यक्ति आय
3. आर्थिक कल्याण
4. आर्थिक विकास के मापक निर्देशांक :
 - (i) सामाजिक अथवा मूलभूत आवश्यकता सूचकांक
 - (ii) क्रयशक्ति समता सूचकांक
 - (iii) मानव विकास सूचकांक
 - (iv) अन्य निर्देशांक

राष्ट्र में शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ रहा है तो वह उसकी है परन्तु यह वृद्धि निरन्तर व स्थायी होनी चाहिए।

इसी तथ्य को रेखाचित्र 1 द्वारा स्पष्ट किया गया है।

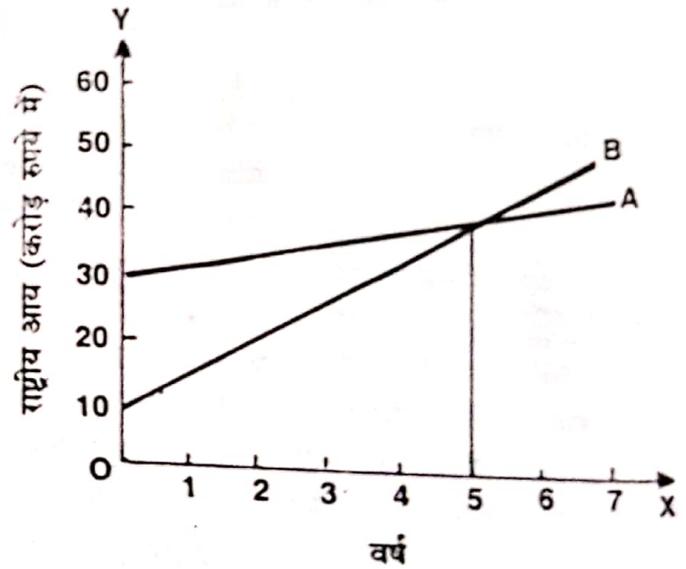
चित्र से स्पष्ट है कि पाँचवें वर्ष तक A देश B देश की तुलना में धनी देश है। पर आरम्भ से ही B देश में राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर A देश की अपेक्षा अधिक है। फलतः पाँचवें वर्ष में पहुँचते-पहुँचते B देश की आय A देश के बराबर हो जाती है और उसके बाद B देश A देश की तुलना में अधिक धनी हो जाता है।

सीमाएँ (Limitations)—राष्ट्रीय आय को आर्थिक विकास के मापन के एक महत्वपूर्ण मापदण्ड के रूप में स्वीकार किया गया है परन्तु इसे सन्तोषजनक नहीं माना जाता है क्योंकि राष्ट्रीय आय की गणना करने में बहुत-सी कठिनाइयाँ आती हैं। जैसे—(i) राष्ट्रीय आय सदैव मुद्रा में ही मापी जाती है परन्तु बहुत-सी वस्तुएँ एवं सेवाएँ ऐसी होती हैं

जिनका मुद्रा में मूल्यांकन करना कठिन होता है। (ii) राष्ट्रीय आय की गणना करने में किसी वस्तु या सेवा को कई बार गिनने की आशंका बनी रहती है। (iii) राष्ट्रीय आय के माप में हस्तान्तरण भुगतान, जैसे—पेशन, बेरोजगारी भत्ता आदि को सम्मिलित करने में कठिनाई उत्पन्न होती है। (iv) राष्ट्रीय आय की परिगणना में बहुत-सी सार्वजनिक सेवाएँ, जैसे—पुलिस व सैनिक सेवाएँ भी ली जाती हैं जिनका ठीक-ठीक हिसाब लगाना कठिन होता है। (v) पूँजीगत लाभ व हानियों को भी राष्ट्रीय आय में आगणन करने में कठिनाई आती है।

2. प्रति व्यक्ति आय—कुछ अर्थशास्त्रियों का मत है कि वास्तविक राष्ट्रीय आय को विकास का एकमात्र सूचक नहीं माना जा सकता। उनका कहना है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से यह सम्भव है कि जन-समूह की निर्धनता बढ़ जाये। ऐसा उस समय होता है जब जनसंख्या में वृद्धि की गति राष्ट्रीय आय में वृद्धि की गति से अधिक तेजी से होती है क्योंकि वास्तविक राष्ट्रीय आय की वृद्धि का अर्थ यह नहीं है कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है। हो सकता है कि लोग बचत की दर बढ़ा रहे हों या फिर सरकार स्वयं इस बढ़ी हुई आय को जनसाधारण की गरीबी को दूर करने के लिए इस्तेमाल कर रही हो। वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि के बावजूद जाने की बजाय मुद्दी भर अमीरों के हाथ में जा रही हो।

आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार अर्द्ध-विकसित देशों की प्रमुख समस्या वहाँ के निवासियों के जीवन-स्तर में सुधार की होती है और जीवन-स्तर में सुधार तभी सम्भव है, जबकि प्रति व्यक्ति आय बढ़े। अतः उनके मत में आर्थिक विकास का सही मापदण्ड प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि है, न कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि।



चित्र 1

प्रति व्यक्ति आय के पक्ष में तर्क—प्रति व्यक्ति आय के पक्ष में निम्न तर्क दिये जा सकते हैं :

(अ) जीवन-स्तर में सुधार (Improvement in Living Standard)—आर्थिक विकास में वर्तमान रुचि का मुख्य कारण अर्द्ध-विकसित देशों के निवासियों का जीवन-स्तर सुधारना है। इसके लिए प्रति व्यक्ति आय का बढ़ना आवश्यक है।

(ब) आर्थिक कल्याण में वृद्धि (Increase in Economic Welfare)—पिछले कुछ वर्षों में जनसंख्या, विशेषकर एशिया के देशों में अत्यधिक बढ़ी है। यदि हम इसकी उपेक्षा कर देंगे तो आर्थिक कल्याण की वृद्धि का कोई अर्थ नहीं होगा। साथ ही विगत वर्षों में जनसंख्या और प्रति व्यक्ति आय दोनों में ही वृद्धि हुई है। इसका यह अर्थ हुआ कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय की अपेक्षा अधिक रही है।

(स) प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि (Increase in Per Capita Production)—आर्थिक विकास के लिए प्रति व्यक्ति उत्पादन बढ़ना अनिवार्य है और इस बढ़ती हुई उत्पादितता का सही सूचक बढ़ती हुई प्रति व्यक्ति आय है, न कि राष्ट्रीय आय।

प्रति व्यक्ति आय के विपक्ष में तर्क—आर्थिक विकास के मापदण्ड के रूप में प्रति व्यक्ति आय के विपक्ष में निम्नलिखित तर्क दिये जा सकते हैं :

(अ) प्रति व्यक्ति आय के बढ़ने के बावजूद प्रति व्यक्ति उपभोग की मात्रा कम होना।

(ब) ऐच्छिक रूप से अथवा अनिवार्य रूप से बचतों का अधिक किया जाना।

(स) धन का असमान वितरण होना इत्यादि। अतः आर्थिक विकास का यह सूचक भी मानव-जाति के अन्तिम लक्ष्य, आर्थिक कल्याण के प्रति तटस्थ बना रहता है।

3. आर्थिक कल्याण (Economic Welfare)—कुछ अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक कल्याण को आर्थिक विकास का उचित मापदण्ड माना है। उनके अनुसार ऐसी प्रक्रिया को आर्थिक विकास माना जाता है जिससे प्रति व्यक्ति वास्तविक आय व उपभोग में वृद्धि होती है और उसके साथ-साथ आय की असमानताओं का अन्तर कम होता है तथा देश के निवासियों को अधिकतम सन्तुष्टि मिलती है। ओकन और रिचर्डसन¹ के शब्दों में, आर्थिक विकास “भौतिक समृद्धि में ऐसा अनवरत् दीर्घकालीन सुधार है जो कि वस्तुओं और सेवाओं के बढ़ते हुए प्रवाह में प्रतिबिम्बित समझा जा सकता है। संक्षेप में, जीवन स्तर मुख्यतः उपभोग के स्तर पर निर्भर करता है। इसलिए देश में बढ़ता हुआ उपभोग व जीवन स्तर ही आर्थिक विकास का अभिसूचक है।

सीमाएँ (Limitations)—इस मापदण्ड की प्रमुख सीमाएँ निम्नलिखित हैं :

(अ) यह आवश्यक नहीं है कि वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि का अर्थ आर्थिक कल्याण में सुधार ही हो क्योंकि हो सकता है कि वास्तविक राष्ट्रीय आय बढ़ने पर भी उसका वितरण न्यायपूर्ण नहीं है जिसके फलस्वरूप गरीबों के उपभोग स्तर में किसी प्रकार की वृद्धि न हो।

(ब) उपभोग तथा जीवन स्तर अत्यन्त भ्रामक शब्द हैं जिनकी निरपेक्ष माप सम्भव नहीं है।

(स) कल्याण के दृष्टिकोण से हमें केवल यह नहीं देखना चाहिए कि क्या उत्पादित किया जाता है बल्कि यह भी कि उसका उत्पादन कैसे होता है। वास्तविक राष्ट्रीय उत्पादन के बढ़ने से सम्भव है कि अर्थव्यवस्था में वास्तविक लागतों (पीड़ा और त्याग) और सामाजिक लागतों में वृद्धि हुई हो। उदाहरणार्थ, उत्पादन में वृद्धि अधिक घण्टे तथा श्रम-शक्ति की कार्यकारी अवस्थाओं में गिरावट के कारण हुई हो तो ऐसी स्थिति में उत्पादन बढ़ने पर भी आर्थिक कल्याण में वृद्धि नहीं होगी।

4. आर्थिक विकास के मापक निर्देशांक (Economic Development Measurement Indices)—विभिन्न अर्थशास्त्रियों, अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं, जैसे—विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum), विश्व बैंक (World Bank) आदि ने विभिन्न सामाजिक व आर्थिक निर्देशांकों के द्वारा विभिन्न देशों के आर्थिक विकास के स्तर को मापने का प्रयास किया है। उनमें से कुछ प्रमुख निर्देशांकों (Indices) का अध्ययन हम नीचे कर रहे हैं :

(i) सामाजिक अथवा मूलभूत आवश्यकता सूचक (Social or Basic Needs Indicator)—विकास के राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति माप से असन्तुष्ट होकर 1970 की दशाब्दी से आर्थिक विचारकों ने विकास प्रक्रिया की गुणवत्ता की ओर ध्यान देना प्रारम्भ किया है जिसके अनुसार वे तीन विभिन्न परन्तु पूरक, रोजगार को

1 Okun and R. W. Richardson, *Studies in Economic Development*, p. 230.

बढ़ाने, गरीबी को दूर करने तथा आय और धन की असमानताओं को कम करने के लिए मूलभूत मानवीय आवश्यकताओं (Basic Human Needs) की कूटनीति पर जोर देते हैं।

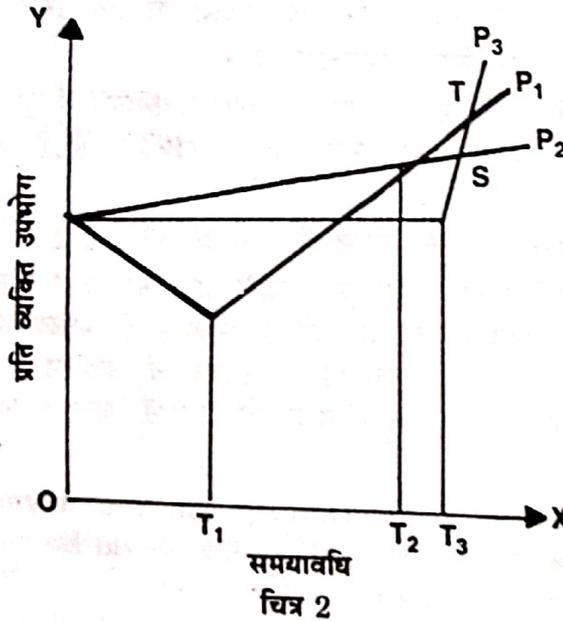
इस कूटनीति के अन्तर्गत मूलभूत न्यूनतम आवश्यकताओं के प्रबन्ध के अतिरिक्त रोजगार के सुअवसरों, पिछड़े वर्गों के उत्थान तथा पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर बल देना और उचित कीमतों एवं दक्ष वितरण प्रणाली द्वारा आवश्यक वस्तुओं को गरीब वर्गों को जुटाना है।

हिक्स और स्ट्रीटन¹ मूलभूत आवश्यकताओं के लिए छः सामाजिक सूचकों पर विचार करते हैं :

मूल आवश्यकता	सूचक
(1) स्वास्थ्य	जन्म के समय जीवन की प्रत्याशा
(2) शिक्षा	प्राथमिक शिक्षा विद्यालयों में जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार दाखिले द्वारा साक्षरता की दर
(3) खाद्य	प्रति व्यक्ति कैलोरी आपूर्ति
(4) जल आपूर्ति	शिशु मृत्यु दर तथा पीने योग्य पानी तक कितने प्रतिशत जनसंख्या की पहुँच
(5) स्वच्छता	शिशु मृत्यु दर तथा स्वच्छता प्राप्त जनसंख्या का प्रतिशत
(6) आवास	कोई नहीं

इस प्रकार इस कूटनीति में आय वृद्धि के साथ-साथ गरीबी, बेरोजगारी, स्वास्थ्य व शिक्षा तथा वितरण विषमताओं को दूर करने के उद्देश्यों को यथोचित स्थान दिया गया है। अनेक अर्द्ध-विकसित देशों के हाल के अनुभवों व अध्ययनों की पृष्ठभूमि में इस कसौटी को न्यायसंगत ठहराया गया है।

फाई, रैनिस तथा स्टुअर्ट² ने नौ देशों का अध्ययन किया जिसके अनुसार उन्होंने पाया कि (अ) ताईवान, दक्षिण कोरिया तथा इण्डोनेशिया में मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ-साथ औसत से अधिक आर्थिक विकास हुआ है। (ब) ब्राजील ने मात्र न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा किया तथा औसत से अधिक आर्थिक विकास किया। (स) सोमानी, क्यूबा, मिस्र तथा श्रीलंका ने मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति बहुत अच्छी तरह से की लेकिन आर्थिक विकास औसत से कम था। (द) केवल एक देश मालदीव ने मात्र न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं के प्रावधान के साथ औसत से कम आर्थिक विकास प्राप्त किया।



चित्र 2

व्यक्ति उपभोग समय T_1 तक घटता है क्योंकि तेजी से औद्योगीकरण से गरीबी, बेरोजगारी, असमानता बढ़ती है परन्तु जब प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के लाभ गरीबों तक 'रिस कर' पहुँचते हैं तो उनके रोजगार तथा आय में वृद्धि होती है और समय T_1 के बाद प्रति व्यक्ति उपभोग में भी वृद्धि होनी शुरू हो जाती है।

1 Normal L. Hicks and Paul. P. Streeten, 'Indicators of Development : The Search for a Basic Needs Yardstick', World Development, Vol. 7, 1979.
2 C. H. Fei, G. Ranis and F. Stewart, Basic Needs : A Framework for Analysis, 1979.

(iii) पथ P_2 का सम्बन्ध आर्थिक कल्याण की धारणा से है जो गरीबों में प्रति व्यक्ति उपभोग की धीमी वृद्धि को दर्शाता है। यह पथ समय T_2 से पथ P_1 से पीछे रहता है।

(iv) पथ P_3 मूलभूत आवश्यकताओं की कूटनीति से सम्बन्धित है जिसमें शुरू में गरीबों में उपभोग के मूलभूत न्यूनतम वेतनमान स्तर को प्राप्त करने को उच्च प्राथमिकता दी जाती है जो समय T_3 तक आर्थिक कल्याण तथा प्रति व्यक्ति आय के उपभोग स्तरों से कम रहता है परन्तु दीर्घकाल में जब गरीबों की मूलभूत आवश्यकताओं के पूरा होने के कारण उनकी उत्पादकता तथा आय के स्तरों में वृद्धि हो जाती है तो समय T_3 से आगे आर्थिक विकास तीव्र गति से होने लगता है।

(v) इस प्रकार पथ P_3 पहले पथ P_2 को R बिन्दु पर पीछे छोड़ देता है तथा बाद में S बिन्दु पर पथ P_1 से ऊपर चला जाता है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि मूलभूत आवश्यकताओं की कूटनीति या मापदण्ड कुल राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय व आर्थिक कल्याण की आर्थिक विकास की कूटनीति से श्रेष्ठ है।

(vi) भौतिक जीवन-कोटि निर्देशांक (Physical Quality of Life Index, PQLI)—कुछ विद्वानों के अनुसार भौतिक जीवन-कोटि में सुधार आर्थिक विकास का संकेतक माना है। मारिश डी मारिश ने एक वर्ष पर जीवन प्रत्याशा, बाल मृत्यु दर (Infant Mortality) तथा साक्षरता तीनों को मिलाकर समन्वित निर्देशांक निर्मित किया जिसे उन्होंने जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक (Physical Quality of Life Index, PQLI) कहा।

इस कूटनीति या संकेतक से बहुत-से सूचकों, जैसे—स्वास्थ्य, शिक्षा, पेय जल, पोषण तथा स्वच्छता आदि का पता चला है। प्रत्येक सूचक के तीनों घटकों को शून्य से 100 तक के पैमाने पर रखा गया है जिसमें शून्य को निम्नतम तथा 100 को सर्वोत्तम प्रदर्शन के रूप में परिभाषित किया गया है। PQLI सूचक की गणना तीनों घटकों को समान भार (Weight) देते हुए औसत निकालकर की जाती है तथा सूचक को भी शून्य से 100 के पैमाने पर रखा गया है।

इस निर्देशांक के आधार पर देश में विकास के होने या न होने का पता चलता है। यदि जीवन-निर्देशांक में स्थायी तौर से वृद्धि होती है जो कि तभी सम्भव है, जबकि देश में कुल राष्ट्रीय उत्पादन का वितरण और उपयोग इस ढंग से हो कि अधिकाधिक लोग लाभ उठा सकें और फलस्वरूप शिशु मृत्यु-दर घटे तथा प्रत्याशित आयु और साक्षरता बढ़े तो यह इस बात का सूचक होगा कि देश में आर्थिक विकास हो रहा है।

अपने अध्ययन में मैरिस ने यह पाया कि प्रति व्यक्ति आय व PQLI के बीच कोई स्वतः तालमेल नहीं होता। उन्होंने पाया कि यद्यपि श्रीलंका का PQLI भारत से कहीं अधिक था, जबकि इसकी औसत प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर लगभग भारत के बराबर थी। इसी प्रकार अमेरिका तथा इटली दोनों ही विकसित देशों का PQLI काफी ऊँचा था परन्तु इटली की प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर अमेरिका से लगभग दुगुनी थी। अतः उनका मत था कि राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय नहीं बल्कि PQLI ही आर्थिक विकास का एक उचित मापदण्ड है।

सीमाएँ (Limitations)

अनेक अर्थशास्त्री इस मापदण्ड की निम्नलिखित आधारों पर आलोचनाएँ करते हैं :

(i) PQLI मूल आवश्यकताओं को केवल एक सीमा तक ही माप सकता है।

(ii) यह मापदण्ड सामाजिक और आर्थिक संगठन के बदले हुए ढाँचे को भी नहीं प्रदर्शित करता है। अतः यह आर्थिक विकास को नहीं मापता।

(iii) इसके अन्तर्गत केवल तीन सूचकों को ही लिया गया है और अनेक सूचकों को छोड़ दिया गया है जो जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं।

(iv) PQLI कुल कल्याण को भी नहीं मापता है।

उपर्युक्त सीमाओं के होते हुए भी PQLI जीवन की गुणवत्ताओं को मापता है जो गरीबों के लिए बहुत आवश्यक है। साथ ही यह अल्पविकास के उन विशेष क्षेत्रों का पता लगाने तथा सामाजिक नीतियों की असफलता तथा उपेक्षा के शिकार समाज के विभिन्न वर्गों की जानकारी प्राप्त करने में सहायक हो सकता है। यह उस सूचक की ओर संकेत करता है जहाँ तत्काल सरकारी हस्तक्षेप व कार्यवाहियों की आवश्यकता होती है। सरकार ऐसी नीतियाँ अपना सकती है जिससे PQLI में भी शीघ्र वृद्धि हो तथा आर्थिक विकास भी त्वरित हो।

(ii) क्रयशक्ति समता सूचकांक (Purchasing Power Parity Index)—आर्थिक विकास के मापदण्ड के रूप में क्रयशक्ति समता सूचकांक का भी उपयोग किया जाता है। इस सूचकांक का सर्वप्रथम उपयोग अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किया था। आजकल विभिन्न देशों के रहन-सहन की तुलना के लिए विश्व बैंक द्वारा इस सूचकांक का उपयोग किया जा रहा है।

क्रयशक्ति समता विधि के अन्तर्गत किसी देश की सकल राष्ट्रीय आय को किसी पूर्ण निश्चित अन्तर्राष्ट्रीय विदेशी विनिमय दर पर न व्यक्त करके, उस देश के भीतर मुद्रा की क्रयशक्ति के आधार पर व्यक्त किया जाता है और विभिन्न देशों के रहन-सहन के स्तर के माप व तुलना के लिए क्रयशक्ति समता स्थापित की जाती है।

क्रयशक्ति समता स्थापित करने की विधि को हम एक उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। मान लीजिए, X तथा Y दो देश हैं जिनका अपनी मुद्रा में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद क्रमशः 30 हजार व 35 हजार है। चूँकि दोनों देशों में अलग-अलग मुद्राओं का प्रचलन है। अतः इनकी तुलना तब तक सम्भव नहीं है जब तक कि इन्हें किसी एक मुद्रा या एक इकाई में बदल नहीं दिया जाता। ऐसा करने के लिए एक सरल तरीका यह होगा कि दोनों देशों की प्रति व्यक्ति घरेलू उत्पाद को किसी अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा जैसे डालर में बदल दिया जाय। मान लीजिए कि दोनों देशों की मुद्राओं के सम्बन्ध में निर्धारित विनिमय दर 1 \$ = 50 है। ऐसी स्थिति में X देश की प्रति व्यक्ति आय 600 डालर तथा Y देश की प्रति व्यक्ति आय 700 डालर होगी। ऐसी स्थिति में यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि चूँकि Y देश में प्रति व्यक्ति की आय अधिक है। इसलिए वहाँ के निवासियों का रहन-सहन का स्तर ऊँचा है।

परन्तु उपर्युक्त निष्कर्ष जिसमें डालर के रूप में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर व्यक्तियों का रहन-सहन या उपभोग का स्तर मापा गया है, यह आवश्यक नहीं है कि वहाँ के निवासियों के जीवन स्तर का सही चित्र प्रस्तुत करे क्योंकि हो सकता है, दोनों देशों में मुद्रा (डालर) की क्रयशक्ति अलग हो जिससे उनकी वास्तविक आय पृथक्-पृथक् होगी।

वस्तुतः रहन-सहन का स्तर वास्तविक आय पर निर्भर करता है और यदि दोनों देशों में डालर की क्रयशक्ति समान नहीं है तो डालर के रूप में व्यक्त की गयी प्रति व्यक्ति आय भ्रामक निष्कर्ष दे सकती है। उदाहरण के लिए, यदि X देश में एक डालर की क्रयशक्ति 20 वस्तुओं व सेवाओं की इकाई है और Y देश में 10 वस्तुओं व सेवाओं की इकाई है तो वास्तविक रूप में परिवर्तित करने पर X देश की प्रति व्यक्ति आय 12,000 वस्तुएँ व सेवाएँ तथा Y देश की प्रति व्यक्ति आय 7,000 वस्तुएँ व सेवाएँ होगी। इस आधार पर सही निष्कर्ष यह प्राप्त होता है कि X देश में उपभोग का स्तर Y देश के उपभोग के स्तर से ऊँचा है। इसीलिए अर्थशास्त्रियों ने क्रयशक्ति समता सूचकांक (Purchasing Power Parity Index) तैयार किया जिसके आधार पर क्रयशक्ति समता के रूप में विभिन्न देशों की प्रति व्यक्ति आय को विश्व बैंक व्यक्त करता है। क्रयशक्ति समता के आधार पर भारत की प्रति व्यक्ति आय 1998 में 1,700 डालर थी और इस आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है परन्तु अधिकांश अर्थशास्त्री क्रयशक्ति समता सूचकांक को आर्थिक विकास की मापन की एक अच्छी विधि नहीं मानते हैं।

(iii) मानव विकास सूचकांक (Human Development Index, HDI)—संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (United Nations Development Programme, UNDP) के साथ जुटे हुए अर्थशास्त्री महबूबल हक ने विकास के एक सर्वमान्य सूचकांक को विकसित करने की दिशा में सबसे पहले प्रयास शुरू किया। उनके कहने पर नोबल पुरस्कार से सम्मानित प्रो. ए. के. सेन तथा प्रो. सिंगर हंस के नेतृत्व में अर्थशास्त्रियों के एक समूह ने मानव विकास सूचकांक (HDI) विकसित किया।

HDI की पूरी धारणा इस मान्यता पर आधारित है कि "किसी राष्ट्र में रहने वाले लोग ही उस राष्ट्र की वास्तविक सम्पत्ति हैं।" आर्थिक विकास का मूल उद्देश्य एक ऐसा वातावरण तैयार करना है जिससे लोग लम्बे, स्वस्थ तथा सृजनात्मक जीवन का आनन्द उठा सकें।

मानव विकास प्रतिवेदन के अनुसार "मानव विकास लोगों की पसन्दगियों के विस्तृत करने की एक प्रक्रिया है।" ये पसन्दगियाँ अनेक हो सकती हैं और इन पसन्दगियों में समय के साथ परिवर्तन हो सकता है, पर विकास के प्रत्येक स्तर पर तीन आवश्यक पसन्दगियाँ हैं और ये हैं—लम्बी और स्वस्थ जिन्दगी जीने की इच्छा, ज्ञान प्राप्त करने की अभिलाषा और एक खूबसूरत जिन्दगी व्यतीत करने के लिए आवश्यक संसाधनों तक पहुँचने की इच्छा। यदि ये तीनों पसन्दगियाँ उपलब्ध नहीं हैं तो व्यक्ति को अनेक अवसरों से वंचित होना

पड़ेगा। अतः व्यक्ति को एक खूबसूरत जिन्दगी व्यतीत करने के लिए (अ) आवश्यकताओं को सन्तुष्ट करने के लिए आय, (ब) शिक्षा तथा (स) स्वास्थ्य आवश्यक है। इस प्रकार HDI तीन आधारभूत पहलुओं में उपलब्धियों का एक मिश्रित सूचक है—एक लम्बा व स्वस्थ जीवन, शिक्षा या ज्ञान तथा उत्कृष्ट जीवन स्तर।

मानव विकास सूचकांक का निर्माण (Construction of HDI)

किसी देश के HDI का मूल्य निकालने के लिए तीन सूचकों को लिया जाता है :

- (1) दीर्घायु जिसे जन्म के समय जीवन की सम्भाव्यता द्वारा मापा जाता है—25 वर्ष तथा 85 वर्ष।
- (2) शैक्षिक योग्यताओं की प्राप्ति जिसे वयस्क शिक्षा (दो-तिहाई भार) तथा प्राथमिक, माध्यमिक व क्षेत्रीय विद्यालयों में उपस्थित अनुपातों (एक-तिहाई भार) के मिश्रण अनुपात—0% से 100%।
- (3) जीवन स्तर जिसे डालर की क्रयशक्ति समता (Purchasing Power Parity) पर आधारित वास्तविक प्रति व्यक्ति GDP द्वारा मापा जाता है।

HDI जीवन की सम्भाव्यता सूचक, शैक्षिक प्राप्ति सूचक तथा समायोजित वास्तविक प्रति व्यक्ति GDP सूचक का सरल औसत सूचक है।¹ इसकी गणना इन तीन संकेतकों के योग को 3 से विभाजित कर निकाली जाती है। इसमें प्रत्येक चर का न्यूनतम तथा अधिकतम मूल्य स्थिर है जिसे घटाकर शून्य (0) तथा एक (1) के बीच पैमाने पर रखा गया है तथा प्रत्येक देश इस पैमाने के किसी न किसी बिन्दु पर आता है। ऐसे देश जिनका HDI मूल्य 0.5 से कम है, उन्हें निम्न स्तर के मानव विकास क्रम में रखा जाता है तथा 0.5 से 0.8 मूल्य वाले देशों को मध्यम तथा 0.8 से ऊपर HDI मूल्य वाले देश उच्च स्तर में गिने जाते हैं। HDI में देशों को उनके प्रति व्यक्ति GDP के आधार पर भी क्रमबद्ध किया जाता है।

(iv) अन्य निर्देशांक (Other Index)—विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum) ने भी आर्थिक विकास के मापक निर्देशांक सुझाए हैं जिसमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं :

(अ) प्रौद्योगिकी निर्देशांक (Technology Index)—यह निर्देशांक किसी देश में प्रौद्योगिकी के स्तर का मापन करता है। इसके अन्तर्गत विदेश से प्रौद्योगिकी का आयात और नवोन्मेष (Innovation) में देशों का भागीदारी को भी सम्मिलित किया जाता है। जिस देश का प्रौद्योगिकी निर्देशांक क्रम निर्धारण में जितना ही कम होता है, उसे उतना ही अधिक विकसित माना जाता है, उदाहरण के लिए, विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum) द्वारा सर्वेक्षित कुल 59 देशों में अमेरिका का प्रौद्योगिकी निर्देशांक 1 था और भारत का 38 था।

(ब) स्टार्ट-अप निर्देशांक (Start-up Index)—यह कारोबार को शुरू करने की अनुकूल स्थितियों का मापन करती है। जिस देश का स्टार्ट-अप निर्देशांक जितना ही कम होगा, उस देश में उद्योग शुरू करने की स्थितियाँ उतनी ही अनुकूल होंगी।

(स) आर्थिक सृजनात्मक निर्देशांक (Economic Creativity Index)—यह निर्देशांक प्रौद्योगिकी निर्देशांक और स्टार्ट-अप निर्देशांक दोनों की सूचना एक साथ देता है। यह निर्देशांक हमें यह बताता है कि किसी देश में प्रौद्योगिकी के स्तर और नवोन्मेष की क्या स्थिति है और देशों में व्यवसाय शुरू करने की स्थितियाँ कहाँ तक अनुकूल हैं। यह निर्देशांक क्रम निर्धारण में जितना ही कम होगा, वह देश उतना ही अधिक विकसित होगा।

(द) संवृद्धि स्पर्धात्मक निर्देशांक (Growth Competitive Index)—इसका उद्देश्य उन घटकों को मापना होता है जो किसी अर्थव्यवस्था की आर्थिक विकास की गति त्वरित करते हैं। इस निर्देशांक में उन परिवर्तनों को जो (1) उत्पादकता स्तर (Productivity Level), (2) संचय की उच्च दरों व नवोन्मेष (High Rate of Accumulation and Innovation) तथा (3) उत्पादकता में सुधार आदि को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। जिस देश का यह निर्देशांक जितना कम होगा, वह देश उतना ही अधिक विकसित होगा।